

मोमिनपुरा क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया सर्वे

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मोमिनपुरा क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कैप लगाकर लोगों की जांच की। अब तक 42 से अधिक लोग पीलिया पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पानी की जांच में ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि से हडकंप मच गया है। मोमिनपुरा सहित नवागढ़, रसूलपुर, जरहागढ़ और श्रीगढ़ वाडों में पीलिया के मरीज सामने आने के बाद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है और तत्काल समन्वित कार्रवाई जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग संभावित मरीजों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहा है। वहीं नगर निगम की जल शाखा ने भी कई स्थानों से पानी के नमूने लिए हैं।

जांव में एमपीएन मानक से अधिक

स्वास्थ्य विभाग ने 10 घरों से पानी के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजे थे। जांच में कुछ नमूनों में 22 से 28 एमपीएन प्रति 100 एमएल तक



बैक्टीरिया पाए गए। विशेषज्ञों के अनुसार क्लोरीनयुक्त पेयजल में एमपीएन की मात्रा शून्य होनी चाहिए। 10 से अधिक एमपीएन संदिग्ध और 50 से अधिक होने पर अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। उन्होंने जांच के लिए नगर निगम और पीएचई वाले फीकल कोलीफॉर्म और ई-कोलाई की मौजूदगी जलजनित बीमारियों का कारण बन सकती है। सीएएमएओ ने रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

‘रिपोर्ट हो सार्वजनिक’ : नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि मानक के

अनुसार पेयजल में एमपीएन शून्य होना चाहिए। 10 से अधिक होने पर पानी संदिग्ध और 50 से अधिक होने पर अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। उन्होंने जांच के लिए नगर निगम और पीएचई वाले फीकल कोलीफॉर्म और ई-कोलाई की मौजूदगी जलजनित बीमारियों का कारण बन सकती है। सीएएमएओ ने रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

विभाग सक्रिय, सुधारात्मक कार्रवाई पर सवाल : स्वास्थ्य विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर जल स्रोत के डिसइंफेक्शन, पाइपलाइन और पंप की जांच तथा संरचनात्मक खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही है। फिलहाल क्षेत्र में जांच और उपचार जारी है। प्रशासन ने लोगों से उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीने की अपील की है।

अमेरा कोयला खदान से 3.5 टन कोयला चोरी का मामला, 15-20 लोगों पर केस दर्ज

—संवाददाता—

लखनपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत SECL की अमेरा ओपन कास्ट कोयला खदान से संगठित तरीके से कोयला चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। खदान प्रबंधक समे लाल धैर्य ने 21 फरवरी 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 20 फरवरी की शाम लगभग 6 बजे चिलबिल गांव निवासी आनंद राम कैवट, आलम साय राजवाड़े सहित 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़कर जबरदस्ती खदान में घुसकर करीब 3.5 टन कोयला चुरा लिया। इस कोयले की अनुमानित कीमत लगभग 17,000 रुपये बताई गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पैदल और मोटरसाइकिलों के जरिए खदान परिसर में घुसे और गाड़ों को धक्का देकर कोयला निकालकर ले गए। यह घटना



सुरक्षा चौकी के पास हुई, शिकायत में कहा गया है कि आरोपी संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं, लखनपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 45/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3), 303(2) और 112(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना अमेरा खदान क्षेत्र में कोयला चोरी के लगातार बढ़ते मामलों की कड़ी है। क्षेत्र में पहले भी ऐसी



घटनाएं घट चुकी हैं, जहां ग्रामीण बड़े पैमाने पर कोयला निकालते पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने चोरी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई है, लेकिन संगठित गिरोहों के कारण चुनौती बनी हुई है।

नकली पुलिस बनकर लूटपाट करने का मामला, जांव में जुटी पुलिस

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर में नकली पुलिस बनकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। रविवार दोपहर तकिया रोड पर बाइक सवार बदमाश ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक युवक से 1130 रुपए छीन लिए और फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पूरन यादव,

निवासी ग्राम करदोनो, थाना लुंड्र, रविवार को किसी काम से बाइक से अंबिकापुर आया था। वह तकिया रोड से गुजर रहा था, तभी पीछे से आए एक अज्ञात बाइक सवार ने उसे रोका।

आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि हेल्मेट नहीं पहनने पर चालान कटेंगे। बातचीत के दौरान उसने चालाकी से युवक की जेब में हाथ डालकर 1130 रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गया।

पांच दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न पुरातत्व और लोक संस्कृति ही राष्ट्र की नींव : अजय चतुर्वेदी

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला ‘सरगुजा का पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य’ का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सरगुजा की सांस्कृतिक धरोहरों को समझने, सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। छत्तीसगढ़ की विरासत को संजोने के लिए सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित कार्यशाला में जिला पुरातत्व संघ के सदस्य और प्रदेशभर से आए लगभग 90 शोधार्थियों एवं इतिहास और पुरातत्व विभाग के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राज्यपाल-पुरस्कृत व्याख्याता जिला पुरातत्व संघ सूरजपुर के सदस्य अजय कुमार चतुर्वेदी ने सरगुजा अंचल की लोक



संस्कृति और उसका संरक्षण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने लोक संस्कृति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि—लोक कला संकट में सरगुजा के पारंपरिक गीत, नृत्य, खोली, रहना सहन, खान पान रीति रिवाज और कलाएं आधुनिकता की दौड़ में खोती जा रही हैं। प्राचीन समय में 70-80 प्रकार के लोक वाद्य प्रचलित थे, जिनकी ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि जंगली

जानवरों को भी प्रभावित कर सकती थी। सरगुजिहा, सादरी सहित कोडकू, कोरवाई, कुडुख जैसी जनजातीय बोलियाँ तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरगुजा की संस्कृति वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुकी है, लेकिन इसे बचाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। अजय चतुर्वेदी में सभी प्रतिभागियों ने सरगुजा की अमूल्य

सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित एवं संवर्धित करने का संकल्प लिया। कार्यशाला के अंतिम दिवस पुरातात्विक स्थल मंहेशपुर का भ्रमण कराया गया।

कार्यशाला में पुरातत्व और इतिहास जगत के अनेक विशिष्ट विशेषज्ञ शामिल हुए, जिनमें बोधगया विश्वविद्यालय के डॉ. सचिन मंदिलवार, विनोद पांडेय (मनेन्द्रगढ़), डॉ. अजय पाल सिंह (अंबिकापुर), डॉ. विनय तिवारी (जशपुर), डॉ. भाग्यश्री दीवान, प्रभात कुमार सिंह (रायपुर) शिरीष मिश्रा सहित कई वरिष्ठ पुरातत्वविदों ने सरगुजा की सांस्कृतिक परतों पर गहन चर्चा की। यह आयोजन न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इसने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों—पुरातत्व, लोककला और भाषाई विरासत—को भूल जाते हैं, तो राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाएगी। कार्यशाला ने छत्तीसगढ़ की पुरातत्व और सांस्कृतिक पहचान को नया बल देते हुए समाज को अपने अतीत से जुड़ने की प्रेरणा दी।

गो तस्करी करने वाले के मंसूबों को पुलिस ने किया नाकाम गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की करवाई

—संवाददाता—

बलरामपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के चांदी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मवेशी को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते बूचड़खाने ले जा रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कार्रवाई करते हुए दो मवेशी तस्करी को

गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 4, 6, 10, छत्तीसगढ़ कृषि पशु, परिरक्षण, अधिनियम 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11* के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी चांदी को मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति ग्राम नावाडीह कला,



पियारटोली के रास्ते से पैदल 03 बैल को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते

हाकते हुए बूचड़खाना झारखंड बॉर्डर की ओर ले जा रहे हैं। प्राप्त हुई सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार थाना चांदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान ग्राम नावाडीह कला पियारटोली पहुंचे जहाँ मेन रोड पर 02 व्यक्ति तीन

बैल को मारते पीटते व हाकते हुए झारखंड ले जा रहे थे, जिसे हमराह स्टाफ के साथ घेराबंदी कर विधिवत हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ पर अपना नाम सुरेंद्र काशी, निवासी धनजी, व कोपल देव निवासी ग्राम करचा, थाना चांदी का होना बताया गया।

अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आया युवक, कट गए दोनों पैर

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आने से युवक का दोनों पैर घटने के ऊपर से कट गया। युवक को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मर्यक तिवारी (24) पिता मनोज नाथ तिवारी, निवासी गोपालपुर, शनिवार शाम दोस्तों के साथ घूमने निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे। रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली कि अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में युवक के दोनों पैर घटने के ऊपर से कट गए। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

युवती ने दिखाई हिम्मत

स्टॉल से बांधकर निकाला बाहर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रेलवे फाटक पार करने के दौरान हुई। ट्रेन की रफतार धीमी थी। सूचना मिलते ही चालक ने ट्रेन रोक दी। पटरी पर युवक गंभीर हालत में पड़ा था, लेकिन शुरुआती समय में कोई आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच कटनी से अंबिकापुर



आ रही एक युवती ने साहस दिखाया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रेन के नीचे जाकर घायल युवक को अपने स्टॉल से बांधा और बाहर खींचकर सुरक्षित स्थान पर लाया। इस दौरान युवक होश में था और बात भी कर रहा था। युवती ने उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछकर परिजनों को घटना की सूचना दी।

पुलिस कर रही जाव

घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिवस उनके गृहग्राम बगिया में धूमधाम, उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कार्यक्रम का किया गया आयोजन



—संवाददाता—
जशपुरनगर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62 वाँ जन्मदिवस उनके गृहग्राम बगिया में धूमधाम, उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बगिया में अपने पर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माता श्रीमती जसमनी देवी का चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उनके जन्मदिवस पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया तथा कहा कि जनस्नेह ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने जन्मदिवस को विशेष और यादगार बनाने के लिए सभी का धन्यवाद

ज्ञापित किया। इस विशेष अवसर पर बगिया स्थित श्री राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा के श्रवण कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय, उनकी माताजी श्रीमती जसमनी देवी, धर्मपत्नी श्रीमती कौशलया साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ व्रत कथा का श्रवण किया तथा ईश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

जन्मदिवस की बधाई देने लोगों का लगा रहा तांता : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आगमन से पूर्व ही उनके गृहग्राम बगिया स्थित गृहनिवास में उनसे मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम नागरिकों में मुख्यमंत्री से भेंट करने और उन्हें शुभकामनाएं देने को लेकर विशेष उत्साह और उत्सुकता देखने को मिली। इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय एवं श्रीमती रायमनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, जिला पंचायत सदस्य श्री कृष्ण कुमार राय सहित



पारंपरिक परिधान में आए पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिवस की बधाई...

बगीचा से आए विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पहाड़ी कोरवा समाज के सदस्य अपने पारम्परिक वेशभूषा एवं तौर-धनुष के साथ उपस्थित हुए, जिससे उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस पर पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में उनके क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य संचालित हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उनके गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और उनके क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्चर्य व्यक्त किया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है।

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पंचायत प्रतिनिधि, नगरीय निकायों के प्रतिनिधिगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.

लाल उमेश सिंह, वनमण्डलाधिकारी शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, प्रशिक्षु आईएफएस सुशी यशस्वी मोर्य तथा अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

अमेरा ओपनकास्ट खदान में रात में चोरी... ट्रांसफॉर्मर जला, 15 मीटर तांबे की केबल चुराई, लाखों का नुकसान

—संवाददाता—

लखनपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल की अमेरा ओपनकास्ट कोयला खदान में अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ी चोरी की चोरों ने ओवरहेड तार में तार फेंककर शॉर्ट सर्किट किया, जिससे 1.6 MVA क्षमता का ट्रांसफॉर्मर जल गया ट्रांसफॉर्मर के साथ ही 15 मीटर लंबी तांबे की केबल भी चुरा ली गई। इस घटना से कंपनी को करीब 5 से 7 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि चुराई गई केबल की कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई जा रही है। अमेरा ओसीपी में खान प्रबंधक समसे लाल धारी ने बताया कि वे अमेरा ओसीपी में खान प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। रात करीब 1 बजे अज्ञात चोरों ने ओवरहेड तार पर तार फेंककर शॉर्ट सर्किट किया, जिससे ट्रांसफॉर्मर का कॉइल जल गया और पूरा ट्रांसफॉर्मर भी आग की चपेट में आ गया। साथ ही 15 मीटर तांबे की केबल चुरा ली गई। इस घटना से खदान में



बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, पंप और लाइट बंद हो गए, जिससे उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ। कंपनी को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। प्रबंधक ने लिखित शिकायत में बताया कि चोरी से कंपनी को 5-7 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जबकि चुराई गई केबल की कीमत 20,000 रुपये है। शिकायत के आधार पर लखनपुर थाना में अपराध क्रमांक 44/2026 दर्ज किया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर चोरों की पतासाजी कर रही है।

देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस के साथ तीन नाबालिग पकड़ा

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर में तीन नाबालिग दोस्तों के पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद होने से हडकंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर हथियार जब्त कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नाबालिगों को हथियार किसने



दिया। कोतवाली थाना प्रभारी शशि सिन्हा ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि रिंग रोड स्थित गाड़ाघाट के पास तीन नाबालिग

देशी कट्टा लेकर घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें हथियार रखने के लिए दिया था। हालांकि किसी वारदात को अंजाम देने की योजना के संबंध में उन्होंने जानकारी नहीं दी है।

धान बोनस प्रकरण : 24.98 लाख की कहानी और 10 साल का सन्नाटा

जांच हुई...आंशिक जमा भी...पर अंतिम कार्रवाई अब भी धुंध में...

- धान बोनस से फसल बीमा तक 24.98 लाख की कहानी और दशकभर की चुप्पी
- जांच,आंशिक जमा और फिर सन्नाटा: संबंधित प्रकरण में फैसला कहाँ है ?
- 186 किसानों की सूची,24.98 लाख की निकासी और अजित मामला—10 साल बाद भी अधूरा सच
- अजित विवाद: जांच रिपोर्ट आई, पैसा जमा हुआ...पर अंतिम कार्रवाई क्यों नहीं ?
- 2014-15 की निकासी, 2016 तक जांच... लेकिन अजित प्रकरण में अंतिम स्थिति अब भी अस्पष्ट
- कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला,फिर भी जवाबदेही पर सवाल कायम

—आंकार पाण्डेय—
सूरजपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है,धान खरीदी बोनस,फसल बीमा और ऋण जैसी योजनाओं के माध्यम से किसान सीधे बैंकिंग प्रणाली से जुड़े रहते हैं,ऐसे में यदि इन मदों से संबंधित राशि के आहरण पर सवाल उठते हैं,तो मामला केवल लेखांकन तक सीमित नहीं रहता,बल्कि विश्वास और जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है,उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के धौरपुर शाखा से संबंधित वर्ष 2014-15 का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें लगभग 24,98,580 की राशि के आहरण और उसके बाद की जांच प्रक्रिया का उल्लेख है। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि: मामला आधिकारिक स्तर पर दर्ज हुआ,जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई,आहरण और आंशिक जमा का रिकॉर्ड है,किसानों की विस्तृत सूची उपलब्ध है,हालांकि,अंतिम निष्कर्ष, पूर्ण वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती, यह रिपोर्ट केवल अभिलेखों में दर्ज तथ्यों पर आधारित है, आगे की स्थिति संबंधित प्राधिकरणों के अभिलेखों एवं आदेशों से स्पष्ट होगी।

जांच प्रतिवेदन:आहरण और समायोजन का विवरण—जांच

प्रारंभिक शिकायत: प्रशासन तक पहुंचा मामला

दस्तावेजों के पृष्ठ 1 पर कलेक्टर,सरगुजा को संबोधित एक शिकायत पत्र संलग्न है,इसमें धान बोनस/फसल बीमा राशि के आहरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया है तथा जांच की मांग की गई है,यह शिकायत इस बात का संकेत देती है कि मामला बैंक स्तर से आगे बढ़कर जिला प्रशासन तक पहुंचा।

विभागीय पत्राचार: जांच के औपचारिक आदेश

दस्तावेजों के पृष्ठ 2-3 एवं पृष्ठ 5 में सहकारिता विभाग एवं संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संलग्न हैं, इनमें आदेश क्रमांक 2213 (15.10.2015) तथा 2820 (22.12.2015) का उल्लेख है,जिनमें धान बोनस/फसल बीमा राशि की निकासी के संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं, पत्राचार में लगभग 24.98 लाख की राशि का उल्लेख दर्ज है,यह स्पष्ट करता है कि विभागीय स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया और औपचारिक जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 से 10 तक विस्तृत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध है, रिपोर्ट के अनुसार:दिनांक 11.03.2015 को फसल बीमा मद से 7,48,492.17 का आहरण दर्ज है, अतिरिक्त रूप से कुल 17,58,000 विभिन्न खातों से निकाले जाने का उल्लेख है, चेकों के माध्यम से समितियों के खातों से राशि आहरित की गई, बाद में कुछ राशि का समायोजन/ जमा दर्शाया गया है,दिनांक 28.06.2016 को 14,22,890 जमा किए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में मिलता है, जांच रिपोर्ट में दर्ज यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आहरण के बाद समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई।

गवाहों के बयान:प्रक्रिया की पुष्टि— जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 11-12

में गवाहों के हस्ताक्षरयुक्त बयान संलग्न हैं,इनमें दर्ज है कि: 11.03.2015 को राशि निकासी हुई,शाखा स्तर पर निर्देशानुसार भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई, भुगतान की स्थिति पर टिप्पणियां दर्ज हैं, ये बयान जांच प्रतिवेदन का हिस्सा हैं और घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं।

किसानों की सूची... नामवार विवरण

जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 से 16 में 186 किसानों की सूची संलग्न है, प्रत्येक किसान का नाम,खाता संख्या,संबंधित राशि अंतिम पृष्ठ पर कुल योग 24,98,580.00 अंकित है,यह आंकड़ा शिकायत और जांच में उल्लेखित राशि से मेल खाता है।



मुख्यमंत्री को ज्ञापन: राजनीतिक स्तर तक पहुंचा मुद्दा

दस्तावेजों के पृष्ठ 13 पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन संलग्न है,ज्ञापन में धान खरीदी बोनस राशि में अनियमितता का उल्लेख किया गया है तथा प्रभावित किसानों की सूची संलग्न होने का उल्लेख है, यह दर्शाता है कि प्रकरण केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रहा।

उपलब्ध दस्तावेजों में दर्ज कार्रवाई

दस्तावेजों के अनुसार:शिकायत दर्ज हुई,विभागीय जांच के आदेश जारी हुए, जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ, आंशिक राशि जमा किए जाने का उल्लेख है, हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों में:अंतिम दंडात्मक आदेश,पूर्ण वसूली का प्रमाण,आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से संलग्न नहीं है।

दस्तावेजों से उभरती समय रेखा

वर्ष/तिथि	घटनाक्रम
03.07.2014	धान खरीदी बोनस संदर्भित अवधि
11.03.2015	फसल बीमा मद से 7.48 लाख आहरण
15.10.2015	जांच आदेश क्रमांक 2213
22.12.2015	आदेश क्रमांक 2820
28.06.2016	14.22 लाख जमा का उल्लेख
यह समयरेखा दर्शाती है कि जांच और आंशिक जमा की प्रक्रिया लगभग दो वर्षों तक चली।	

अनुरितित प्रश्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर कुछ प्रश्न उभरते हैं...

- क्या पूरी 24,98,580 की राशि की वसूली हुई?
- क्या विभागीय जांच का अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक किया गया?
- क्या किसी प्रकार की सेवा संबंधी कार्रवाई (निलंबन/बर्खास्तगी) हुई?
- क्या आपराधिक मामला दर्ज हुआ?
- क्या सभी 186 किसानों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित हुआ?

अंतरराष्ट्रीय रेफरी मोहम्मद गौस बेग पुलिस गेम्स में करेंगे निर्णायक की भूमिका

74 वीं ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व

—संवाददाता—
सूरजपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित 74वीं अंतर ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 23 से 27 फरवरी 2026 तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) में आयोजित की जा रही है, इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों की महिला एवं पुरुष टीमों हिस्सा ले रही हैं, इसके अलावा बी एस एफ, सी आई एस एफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसी अर्द्धसैनिक बलों की टीमों भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं,इस राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में सूरजपुर जिले के अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी मोहम्मद गौस बेग को निर्णायक (रेफरी) के रूप में चयनित किया गया है। ये इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया चयन—वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए देश के अनुभवी और प्रमाणित रेफरी का चयन किया जाता है, इसी क्रम में सरगुजा संभाग के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी मोहम्मद गौस बेग को इस बार पुलिस गेम्स में



जिम्मेदारी सौंपी गई है,उनका चयन न केवल सूरजपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है।

व्यापक अनुभव और राष्ट्रीय पहचान—मोहम्मद गौस बेग को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने का अनुभव है। इसके साथ ही वे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित देश की प्रमुख प्रतियोगिताओं में भी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें शामिल हैं—सौनियर नेशनल चैंपियनशिप,नेशनल गेम्स,फेडरेशन कप,यूथ, जूनियर, सब-जूनियर एवं मिनी चैंपियनशिप,अंतर सर्विसेज प्रतियोगिता, विभिन्न राज्यों में आयोजित ऑल इंडिया प्रतियोगिताएं, सैकड़ों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मैचों में सफल संचालन का अनुभव उन्हें देश के प्रमुख रेफरी में स्थान दिलाता है।

पूर्व में भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी—ऑल इंडिया पुलिस गेम्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पूर्व संस्करणों— पटना (बिहार),करनाल (हरियाणा) और भिलाई (छत्तीसगढ़)—में भी गौस बेग निर्णायक की भूमिका निभा चुके हैं, हर बार उन्होंने निष्पक्ष और कुशल संचालन के लिए सराहना प्राप्त की।

सूरजपुर और छत्तीसगढ़ का गौरव—उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गौस बेग छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र सक्रिय अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी हैं। उन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, उनकी यह उपलब्धि सूरजपुर जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश के खेल जगत के लिए प्रेरणादायक है। खेल प्रेमियों और खेल संघों ने उनके चयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उच्चल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

खेल जगत में बढ़ता मान-पुलिस गेम्स जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाना किसी भी रेफरी के लिए सम्मान की बात होती है,मोहम्मद गौस बेग का यह चयन दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभागी ही नहीं, बल्कि अनपेक्षित भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

दो पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई प्रारंभिक पीएससी परीक्षा 12 परीक्षा केन्द्रों में कुल 8973 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रारंभिक पीएससी परीक्षा जिले के 12 परीक्षा केन्द्रों में आज शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में दो पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा,गोपनीयता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। प्रथम पाली में कुल 5601 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 4515 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 1088 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में भी 5601 पंजीकृत



परीक्षार्थियों में से 4460 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 1141 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 8973 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।

परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश से पूर्व सघन जांच की गई तथा आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन

कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक दलों एवं उड़नदस्ता टीमों ने परीक्षा केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण किया। संपूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में रही। प्रशासन की सतर्कता एवं समन्वय से परीक्षा शांतिपूर्ण,पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

प्रॉक्सि राजनीति पर विराम : महिला नेतृत्व को स्वतंत्रता देने की दिशा में बड़ा फैसला

रिश्तेदारी से ऊपर नियम: स्वास्थ्य मंत्री का प्रशासनिक सख्ती वाला निर्णय...

नियम बनाम विवाद : विधायक प्रतिनिधि हटाने के फैसले से एमसीबी की राजनीति में हलचल...

महिला सशक्तिकरण के नाम पर सख्त संदेश : परिजन को पद से हटाया...

विवाद से दूरी या नियम प्राथमिकता? मंत्री के फैसले पर राजनीतिक बहस तेज...

शासन के निर्देशों का पालन: मर्नेद्रगढ़ में विधायक प्रतिनिधि पद पर बड़ा बदलाव...

संवाददाता—
मर्नेद्रगढ़ (एमसीबी), 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मर्नेद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की राजनीति में हल ही में लिया गया एक प्रशासनिक निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है,प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मर्नेद्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल ने मर्नेद्रगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष के लिए सरजू यादव को विधायक प्रतिनिधि के पद से कार्यमुक्त कर दिया, इस फैसले को लेकर विभिन्न स्तरों पर बहस चल रही है—क्या यह केवल नियमों के पालन की प्रक्रिया है,या इसके पीछे राजनीतिक संदर्भ भी हैं? जिम्मेदारी की दृष्टि से देखा जाए तो यह निर्णय कई आयामों से जुड़ा हुआ है—कानूनी, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक। बता दे की छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में'जीरो टॉलरेंस'और 'पारदर्शिता' की गूंज अब धरातल पर दिखने लगी है, प्रदेश के कड़ावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र मर्नेद्रगढ़ में नियमों पर सख्ती से अमल की शुरुआत कर दी है,नगरीय प्रशासन विभाग के उस निर्देश पर, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों और रिश्तेदारों (प्रॉक्सि) के दखल पर रोक लगाई गई थी, मंत्री जायसवाल ने कड़ा फैसला लेते हुए नगरपालिका परिषद मर्नेद्रगढ़ में विधायक प्रतिनिधि के पद से सरजू यादव की जगह भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र पाल सिंह को नया विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, यह फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा 'पॉलिटिकल मैसेज' माना जा रहा है।

कानूनी एवं प्रशासनिक आधार

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी पत्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदारों/नातेदारों को प्रॉक्सि प्रतिनिधि या लायजन पर्सन के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए,12 दिसंबर 2025 के विभागीय पत्र (File No. VIGI-2904/2/2025-UAD) में यह उल्लेखित है कि महिला जनप्रतिनिधियों के कार्यों में उनके परिजनों के हस्तक्षेप पर रोक सुनिश्चित की जाए,प्रतिनिधि नियुक्त करने संबंधी आदेश 20 अगस्त 2010 के पूर्व आदेश में भी कहा गया था कि महिला पदाधिकारियों के कार्य संचालन में उनके संबंधियों की बैठक या निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रतिबंधित है, प्रतिनिधि नियुक्त करने संबंधी था...इन आदेशों का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को व्यवहारिक रूप देना,हितों के टकराव को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है,यदि उक्त निर्देश लागू होते हैं,तो संबंधित पद पर परिजन की नियुक्ति स्वतः नियम-विरुद्ध स्थिति बन जाती है। ऐसे में प्रतिनिधि को हटया जाना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा।

स्थानीय राजनीतिक संदर्भ—मर्नेद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो मंत्री का गृह क्षेत्र है, उसमें प्रमुख नगरीय निकाय—मर्नेद्रगढ़ नगरपालिका,चिरमिरी नगर निगम,झगराखांड नगर पंचायत राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार,विधायक प्रतिनिधि को हटाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आए हैं, कुछ इसे'अमृतधारा महोत्सव' के बाद उत्पन्न चर्चाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि आधिकारिक स्तर पर इसे शासन के नियमों के अनुपालन की कार्रवाई बताया गया है,जिम्मेदार पत्रकारिता की दृष्टि से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस निर्णय को किसी एक आदेशों में संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 की भावना का उल्लेख करते हुए महिला प्रतिनिधित्व की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई है, क्या मंत्री संभावित विवादों से दूरी बनाना चाहते थे? या यह कदम पूरी तरह नियम आधारित है? राजनीतिक जीवन में

सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नियमों की अनदेखी आलोचना का कारण बन सकती है,वहीं,नियमों का पालन करने से प्रशासनिक विश्वसनीयता मजबूत होती है, यदि नियमों के स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं और स्थिति उनसे मेल नहीं खाती,तो कार्रवाई अपेक्षित मानी जाती है,इस संदर्भ में मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय नियम पालन की श्रेणी में रखा जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण का व्यापक आयाम—नगरीय निकायों में महिला आरक्षण का उद्देश्य केवल पद पर चयन नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णय क्षमता देना है,शासन के आदेशों में संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 की भावना का उल्लेख करते हुए महिला प्रतिनिधित्व की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई है, प्रतिनिधि नियुक्त करने संबंधी,यदि परिजन औपचारिक या अनौपचारिक रूप से निर्णय प्रक्रिया संचालित करते हैं,तो आरक्षण की



प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मर्नेद्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल



प्रमिला यादव अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मर्नेद्रगढ़



सरजू यादव पूर्व विधायक प्रतिनिधि



नया विधायक प्रतिनिधि महेंद्र पाल सिंह

मूल भावना प्रभावित होती है,इस दृष्टि से देखा जाए तो यह निर्णय महिला नेतृत्व को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देने की दिशा में कदम माना जा सकता है।

यह निर्णय तीन स्तरों पर प्रभाव डाल सकता है...

- प्रशासनिक स्तर - शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का संदेश।
- संगठनात्मक स्तर-परिवारवाद की धारणा से दूरी।
- राजनीतिक स्तर-पारदर्शिता और जवाबदेही की छवि को मजबूत करना, हालांकि, अंतिम मूल्यांकन समय और आगे की कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा।

संश्लित दृष्टिकोण की आवश्यकता

मर्नेद्रगढ़ में विधायक प्रतिनिधि पद से हटाने की घटना को केवल राजनीतिक चरम से देखना उचित नहीं होगा,उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की गई है, साथ ही, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे नियमों का समान रूप से पूरे प्रदेश में अनुपालन हो, ताकि पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य सार्थक रूप में प्राप्त हो सके, जिम्मेदारी की समझ यही कहती है कि—नियम यदि बने हैं, तो उनका पालन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, और यदि यह पालन निरंतर बना रहता है,तो इससे राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता और सुदृढ़ होगी।

मंत्री वाली सुरक्षा या फोटो का फ्रेम ?
सूरजपुर में वायरल तस्वीर पर सियासी चर्चा
सुरक्षा किसकी, शो किसका ? मंत्री स्टाइल एंट्री

वार्ड 11 में + अंदाज!

लाल झंडा, सशस्त्र गार्ड और पार्षद पति आगे—
सूरजपुर की तस्वीर ने बढ़ाया सियासी तापमान
वार्ड 11 से निकली वीआईपी चाल

पार्षद पति की 'वीआईपी एंट्री' ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल

सुरक्षा किसकी, जिम्मेदारी
किसकी ? यहाँ तीन
संभावनाएँ चर्चा में हैं...

1. कार्यक्रम स्थल की सामान्य तैनाती

संभव है कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री की मौजूदगी रही हो और सुरक्षा कर्मी पूरे परिसर में तैनात रहे हों, ऐसे में फोटो का एंगल भ्रम पैदा कर सकता है।

2. फ्रेम का कमाल

कभी-कभी कैमरा वहीं दिखाता है, जो कहानी बन सके, सुरक्षा कर्मी पीछे खड़े हों और आगे कोई भी व्यक्ति हो—फोटो वीआईपी एंट्री का भ्रम पैदा कर देती है।

3. विशेष सुरक्षा ?

यदि वास्तव में किसी गैर-पदाधिकारी को मंत्री-स्तर की सुरक्षा दी गई हो, तो उसका आधिकारिक आदेश होना चाहिए, बिना प्रशासनिक स्वीकृति ऐसा संभव नहीं।

—ऑंकार पाण्डेय—

सूरजपुर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर की राजनीति इन दिनों विकास, बजट या योजनाओं से नहीं, बल्कि एक फोटो से गरमाई हुई है, तस्वीर में नगर पालिका वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पति आत्मविश्वास भरी चाल में आगे बढ़ते दिखते हैं—काला चश्मा, सधी हुई चाल—और पीछे दो सशस्त्र सुरक्षा कर्मी, जैसे किसी बड़े प्रोटोकॉल का हिस्सा हों, बस फिर क्या था—सोशल मीडिया ने इसे वार्ड लेवल + सुरक्षा घोषित कर दिया।

दृश्य ऐसा... जैसे मंत्री आगमन हो...

फोटो में पीछे खड़ी गाड़ी पर लाल झंडा भी दिखाई देता है, सुरक्षा कर्मियों के पास राइफल और वायरलेस सेट साफ नजर आ रहे हैं, दृश्य ऐसा कि आम नागरिक को लगे—लगता है कोई कैबिनेट स्तर का दौरा है! सूत्रों की फुसफुसाहट कहती है कि ये सुरक्षा कर्मी राज्य की लक्ष्मी राजवाड़े (महिला एवं बाल विकास विभाग) की सुरक्षा ड्यूटी से जुड़े बताए जाते हैं, यदि ऐसा है, तो व्यंग्य का तीर सीधा सवाल पर जा लगता है—मंत्री की सुरक्षा, लेकिन फ्रेम में पार्षद पति?



नियम क्या
कहते हैं ?

सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन और शासन के आदेश पर आधारित होती है, मंत्री, विधायक या संवेदनशील पदों पर बैठे व्यक्तियों को निर्धारित श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, नगर निकाय के पार्षद या उनके परिजन सामान्यतः इस श्रेणी में नहीं आते, ऐसे में सवाल उठता है—क्या यह दृश्य केवल एक संयोग है, या सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्याख्या का नया अध्याय?

प्रशासन से अपेक्षित स्पष्टता

जनता जानना चाहती है: उस दिन कार्यक्रम में कौन उपस्थित था? सुरक्षा कर्मी किस ड्यूटी चार्ट पर थे? क्या कोई विशेष सुरक्षा आदेश जारी हुआ था? जब तक इन सवालों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक यह फोटो चर्चा और तंज का विषय बनी रहेगी।

फोटो से बड़ी है पारदर्शिता

एक तस्वीर राजनीति की पटकथा बदल सकती है—या कम से कम चर्चा जरूर छेड़ सकती है, सूरजपुर की यह वायरल तस्वीर भी शायद एक क्षण का दृश्य हो, या स्थानीय सत्ता समीकरणों की झलक, पर लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं, सवाल यही है—यह सुरक्षा असली थी, संयोग था, या सिर्फ फ्रेम की कहानी? जब तक जवाब नहीं आता, तब तक वार्ड 11 की यह वीआईपी चाल चर्चा का केंद्र बनी रहेगी।

सोशल मीडिया का व्यंग्य

अब वार्ड पार्षद पति को भी एस्कॉर्ट मिलेगा!

लाल बत्ती की कमी रह गई बस...

सूरजपुर में सुरक्षा का लोकतंत्रीकरण! व्यंग्य भले चुभता हो, पर वह सवाल भी उठता है।

खड़गवां में करोड़ों की सड़क पर सवाल

पाँच दिन में उखड़ी परत, ग्रामीणों ने
उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग



—राजेंद्र शर्मा—

खड़गवां (एमसीबी), 22
फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के खड़गवां क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बन रही सड़कों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ठगगाव से करवा पहुंच मार्ग की अनुमानित लागत लगभग 3.39 करोड़ बताई जा रही है, जबकि ठगगाव से तेदुंडा मार्ग का निर्माण एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा कराया जा

रहा है। दोनों परियोजनाएँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य स्तरीय जन-मन से सड़क निर्माण कार्यक्रम के तहत संचालित बताई जा रही हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के कुछ ही दिनों में सड़क की डामर परत उखड़ने लगी है, गिट्टी सतह पर दिखाई दे रही है और कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क की हालत पाँच दिन में ही बिगड़ गई, तो आने वाले मानसून में क्या होगा?

ग्रामीणों की मांग...

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि: संबंधित सड़कों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए, दोष सिद्ध होने पर संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो, क्षतिग्रस्त हिस्सों का मानकों के अनुरूप पुनर्निर्माण कराया जाए, भविष्य में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और नियमित गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण व्यवस्था पर भी उठे प्रश्न

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित रहा, यदि नियमित गुणवत्ता परीक्षण, सैंपल जांच और थर्ड-पार्टी ऑडिट हो, तो ऐसी शिकायतों की गुंजाइश कम हो सकती है, लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी समय पर स्थल निरीक्षण नहीं करते, जिससे ठेकेदारों को मनमानी का अवसर मिलता है।

आवागमन और
सुरक्षा पर प्रभाव

सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में कठिनाई हो रही है, स्कूली छात्र-छात्राएँ, किसान और मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन जोरिख में हैं, जगह-जगह गड्ढे बनने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है।

जवाबदेही का इंतजार

सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिले। लेकिन यदि निर्माण की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में हो, तो योजनाओं की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है, अब देखा होगा कि संबंधित विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या करोड़ों की लागत से बनी यह सड़क वास्तव में ग्रामीणों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ साबित होगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

भाजपा को झटका या संगठन की नई शुरुआत ?

झगराखांड में युवाओं के कांग्रेस प्रवेश से बदला सियासी माहौल



—संवाददाता—
मनेंद्रगढ़, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

क्षेत्रीय राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत झगराखांड और आसपास के पंचायत क्षेत्रों में आयोजित बैठकों ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है, नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरव मिश्रा के नेतृत्व में हुए आयोजनों में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसे राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं, यह अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बृथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित करना है।

पंचायतों से शहर तक संगठन विस्तार

सूत्रों के अनुसार, बंजी, बुंदेली, पागडोल, छिपछिपी, भौता नारायणपुर और तेंदुंडा जैसे पंचायत क्षेत्रों में भी जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, बैठकों में कार्यकारिणी गठन, घर-घर जनसंपर्क, जनसमस्याओं के समाधान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तय की गई, ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मनेंद्रगढ़ शहर द्वारा आयोजित इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और बदलता समीकरण

राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के तीन नगर पंचायत अध्यक्ष — ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रजनीश पांडेय एवं रीमा रमेश यादव — भाजपा में शामिल हो चुके थे, ऐसे परिदृश्य में झगराखांड में युवाओं का कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना संगठन के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।



अजीत सिंह का प्रवेश

बैठक के दौरान अजीत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा और क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर संगठन से जुड़े हैं तथा जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे।

नेतृत्व का संदेश

ब्लॉक अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की असली ताकत है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा जनसंवाद स्थापित करने और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया, मंडलम अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने युवाओं की भागीदारी को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि मजबूत जमीनी रणनीति से संगठन और सशक्त होगा।

प्रमुख उपस्थिति

कार्यक्रम में छोटे लाल वर्मा, राधे मिश्रा, ज्ञानेंद्र सिंह, योगेंद्र खैरवार, राम गोपाल यादव, राकेश यादव, कोमल कांत, खोनेश्वर प्रसाद, मो. रहमतुल्ला, संजय यादव, अरुणिमा सिंह, बबिता यादव, मो. सुलेमान, राज यादव, विनोद जांगड़े, राम राशिले, जगदीश प्रसाद, भावेश जैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आगे क्या ?

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति की दिशा प्रभावित कर सकता है, संगठनात्मक सक्रियता और युवा भागीदारी यदि इसी तरह जारी रही, तो इसका प्रभाव आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है, फिलहाल इतना स्पष्ट है कि नए नेतृत्व में कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ा रही है और झगराखांड सहित पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बगिया में एक आरोग्य अमृत अवलेहश का किया शुभारंभ

—संवाददाता—

जशपुरनगर, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विगत दिवस 21 फरवरी को आरोग्य अमृत अवलेह का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह उत्पाद आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा एवं आधुनिक आवश्यकताओं के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

आरोग्य अमृत अवलेह एक विशेष रूप से निर्मित आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है, जो पारंपरिक Chyawanprash की श्रेष्ठता से प्रेरित है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह शरीर की प्राकृतिक रोग-



प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक हो। साथ

ही यह स्मरण शक्ति, एकप्रज्ञा एवं मानसिक स्फूर्ति को बढ़ाने में भी उपयोगी है। वर्तमान समय की भागदौड़ एवं तनावपूर्ण जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए यह उत्पाद सभी आयु वर्ग के लिए लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन आयुर्वेद, वनोपधि एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, ताकि आमजन स्वस्थ एवं सशक्त जीवन व्यतीत कर सकें। शरारोग्य अमृत अवलेह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़

औषधीय वनस्पतियों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है और यहां उपलब्ध वन संपदा का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग कर स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सलिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास डीएफओ श्री शशि कुमार जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमुदाय ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे राज्य की स्वास्थ्य उन्नयन दिशा में एक सराहनीय कदम बताया।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH,
WATER RESOURCES DEPARTMENT

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER WATER
RESOURCES DIVISION, KUNKURI (C.G.)

CORRIGENDUM NO. 1

IN NIT No. 09/SAC/2025-26, Dated 11.02.2026, System Tender No. 185415 (2nd Call) whose G-Number- 252606651 following amendments are made-

S.NO	Amendments
1	Bid Start date & time 20.02.2026 at 17:31 Hours.

All other terms and conditions of NIT will remain unchanged.

जी नंबर-252606801/5

Executive Engineer Water
Resources Division Kunkuri (C.G.)

शिलान्यास से शर्मनाक तक कोरिया उत्सव में श्रेय ऊपर, जवाबदेही नीचे

तालियों का उत्सव, जिम्मेदारी का पतन: दूरी पट्टिकाओं ने खोली प्रशासन की पोल



फोटो में फंटे, कार्रवाई में बैक सीट: किसे बचाया, किसे बनाया बलि कब बकरा ?

उद्घाटन भव्य...समापन विडंबना: विकास के बोर्ड धूल में...जिम्मेदारी फाड़ल में...

श्रेय की होड़, जवाबदेही से मोहभंग : कोरिया में प्रशासनिक संतुलन पर सवाल

तालियां सबकी, सजा एक की... ? कोरिया उत्सव के बाद उठे तीखे प्रश्न

सोशल मीडिया... नया लोकपाल

मैदान में पड़ी पट्टिकाओं का वीडियो वायरल हुआ, जिस उपलब्धि को प्रेस नोटों में सजाया गया था, उसे जनता ने मोबाइल कैमरे से परखा, अब डिजिटल दौर में न तो श्रेय छिपता है, न चूक, सोशल मीडिया ने इस बार उत्सव को उपहास में बदल दिया।

प्रशासनिक गणित: श्रेय ऊपर, सजा नीचे ?

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या कार्रवाई का पैमाना समान है? यदि आयोजन सामूहिक था, तो समीक्षा भी सामूहिक क्यों नहीं? यदि शीर्ष स्तर पर निगरानी थी, तो जवाबदेही भी वहीं से क्यों न शुरू हो? व्यंग्य यही कह रहा है-जब मंच पर माला पहननी हो तो सब आगे, जब जवाब देना हो तो फाइल नीचे भेज दो।

क्या यह पहले से तय पटकथा थी ?

जिले में यह चर्चा भी है कि नियमित अधिकारियों को किनारे कर प्रभारी व्यवस्था को आगे लाने की रणनीति पहले से तैयार थी, अब दोनों प्रमुख स्थानों पर नियमित की जगह प्रभारी की कमान की संभावना बताई जा रही है, विडंबना देखिए-नियमित अधिकारी संलग्न और प्रभारी सक्रिय। यह प्रशासनिक पुनर्संरचना है या अवसरवाद-यह समय बताएगा।

पट्टिका टूटी या व्यवस्था ?

कोरिया का यह मामला केवल टूटी शिलान्यास पट्टिकाओं का नहीं है, यह उस सोच का आईना है जिसमें सफलता का मंच साझा होता है, लेकिन असफलता का कटघरा एकतरफा, जनता की मांग सरल है, कार्रवाई हो तो निष्पक्ष हो, जवाबदेही तय हो तो ऊपर से शुरू हो, क्योंकि विकास केवल घोषणा से नहीं, व्यवस्था से चलता है, और व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब-मोहरा नहीं, मापदंड बदले जाएं।

-रवि सिंह-
कोरिया, 22 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के दौरे से लेकर स्वयं मुख्यमंत्री के आगमन तक जिला प्रशासन ने जिस फुर्ती, सजगता और फोटो-प्रबंधन का परिचय दिया, वह किसी बड़े राष्ट्रीय आयोजन से कम नहीं था, मंच सजा, बैनर चमके, भाषण गुंजे और कैमरे इतने सक्रिय रहे मानो विकास का असली उद्घाटन लेंस के सामने ही होना हो, लेकिन समापन के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे उत्सव को व्यंग्य में बदल दिया-मैदान में धूल फांकती, टूटी और बिखरी शिलान्यास पट्टिकाएं, जिस विकास को मंच से ऐतिहासिक बताया गया, वह मैदान में प्रतीकात्मक होकर रह गया।

बात दे की राजस्व विभाग किस तरह अन्य विभागों को कुचलता है, किस तरह वह अन्य विभागों को निचले दर्जे का और केवल उपयोगी मानता है इसका ताजा उदाहरण कोरिया जिले से देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कोरिया जिले में मुख्यमंत्री के आगमन और तीन दिवसीय उत्सव के आयोजन समापन उपरान्त अब गलतियों के लिए जनपद सीईओ बैकूंटपुर को पद से हटाकर जिला संलग्न किया जा रहा है, उनको जगह अब कलेक्टर कोरिया की पसंद का प्रभारी सीईओ जिम्मेदारी सम्हाल सकता है, बताया जा रहा है कि शासन से सीधे नियुक्त जनपद सीईओ सोनहत और बैकूंटपुर दोनों ही कलेक्टर कोरिया को नापसंद थे और जिसके कारण वह उनसे नाराज चल रही थीं और सोनहत सीईओ को हटा चुकी कलेक्टर को बैकूंटपुर सीईओ को हटाने का मौका अपने मन पसंद प्रभारी सीईओ को लाने का मौका नहीं मिल रहा था और इस मौके की तलाश आखिर कार पूरी की गई और जनपद सीईओ को बेवजह अब हटा दिया गया, जनपद सीईओ को कोरिया उत्सव में लापरवाही, कार्य उदासीनता के लिए हटाया गया है, और यह ऐसी उदासीनता है जो लागू अन्य विभागों पर होनी चाहिए लेकिन इसे जनपद सीईओ पर लागू किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए पट्टिकाओं का

पट्टिकाएं कई विभागों की...कार्रवाई सिर्फ जनपद सीईओ पर क्यों ?

कांग्रेस नेता द्वारा वायरल किए गए वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैदान में पड़ी और टूटी शिलान्यास पट्टिकाएं केवल एक विभाग की नहीं, बल्कि कई विभागों से संबंधित थीं। सवाल स्वाभाविक है-जब पट्टिकाएं सामूहिक थीं तो जवाबदेही एकल कैसे हो गई? यदि आयोजन बहु-विभागीय था, शिलान्यास विभिन्न योजनाओं के थे और जिम्मेदारी साझा थी, तो कार्रवाई भी साझा क्यों नहीं दिखी? चर्चा यह भी है कि जिस अधिकारी पर सीधी जिम्मेदारी थी उसे केवल कारण बताओ नोटिस देकर औपचारिकता पूरी कर ली गई, जबकि जनपद सीईओ को हटाकर संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई, जिले में यह फुसफुसाहट भी है कि जहां एजेंडार मंजूर नहीं था, वहां नोटिस काफी था...और जहां व्यवस्था बदली जानी थी, वहां कार्रवाई जरूरी हो गई, अब सवाल यह है-क्या यह महज प्रशासनिक चूक है, या फिर पहले से तय पटकथा का हिस्सा?

धर्मपत्नी से मुख्यमंत्री तक: कार्यक्रमों में प्रशासन की लड़खड़ाहट

मुख्यमंत्री के आगमन से पहले उनकी धर्मपत्नी का दौरा हुआ, भीड़ जुटाने की तैयारी हुई, स्वागत की औपचारिकताएं पूरी की गईं। लेकिन जैसे ही वे मंच पर पहुंचीं, भीड़ का बड़ा हिस्सा पलायन करता नजर आया। मंच से कटाक्ष भी हुआ-जो प्रशासनिक तैयारी पर अत्यधिक टिप्पणी माना गया, उस समय प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बताकर किनारा किया। पर वहीं असंगति आगे भी दिखी, मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान भी कई अवसरों पर व्यवस्थागत चूक सामने आई-भीड़ प्रबंधन, समन्वय, और अंततः शिलान्यास पट्टिकाओं की दुर्दशा, लगातार दो महत्वपूर्ण दौरों में सामने आई असंगतियां यह संकेत देती हैं कि समस्या किसी एक अधिकारी या एक घटना तक सीमित नहीं थी। सवाल उठता है-क्या प्रशासन कार्यक्रमों की चमक में उलझा रहा और व्यवस्थाओं की बुनियाद कमजोर रह गई?

प्रमोशन की राजनीति या प्रशासनिक प्रदर्शन ?

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से लेकर मुख्यमंत्री तक के दौरे की रूपरेखा प्रशासनिक स्तर पर अत्यंत सक्रियता से तैयार की गई थी। इसे केवल आयोजन नहीं, बल्कि प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है-जहां वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह अवसर था अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने का, मंचीय उपस्थिति, प्रोटोकॉल प्रबंधन और फोटो फ्रेम में सक्रियता-सब कुछ व्यवस्थित दिखा। लेकिन जैसे ही दोनों की रवानगी हुई, वास्तविक स्थिति सामने आने लगी, घूघरा में भीड़ का अभाव, वन विभाग विश्राम गृह में देर रात विवाद की चर्चा, और अंततः मैदान में बिखरी शिलान्यास पट्टिकाएं-इन सबने उस सफल आयोजन की परतें उधेड़ दीं, जिसे प्रशासन उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, व्यंग्य यही कहता है-जब तक वीआईपी रहे, सब व्यवस्थित रहा, जाते ही व्यवस्था भी साथ चली गई।

मैदान में पड़े मिलना, टूट जाना और पांव के नीचे आना गलती और चूक मानी गई है, वैसे क्या पूरे आयोजन का जिम्मेदार जनपद सीईओ को बनाया गया था यह सवाल शेष रह गया इस कार्यवाही के दौरान, वैसे आयोजन स्थल वाले मैदान में शिला पट्टिकाओं की टूटी स्थिति कांग्रेस नेता ने सामने लाई उसके पहले पूरा जिला प्रशासन अपनी पीठ सफल आयोजन के लिए थपथपा रहा था जिसमें पदोन्नति की आस थी, पुरस्कार की अभिलाषा थी, आयोजन का श्रेय राजस्व विभाग को था लेकिन जैसे ही कार्यवाही की बात सामने आई वैसे ही बलि का बकरा सीईओ जनपद को बनाया गया, शेष जो असल जिम्मेदार थे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर मामले में कार्यवाही संतुलन समिति किया गया, पूरे मामले में राजस्व विभाग को बचाने खेल हुआ यह अब सामने है।



पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी एसडीएम ने खुद को बचाया, सीईओ जनपद को निपटारा ?

सवाल यह भी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी एसडीएम ने सीईओ जनपद को निपटारा है, माना यही जा रहा है, मामला पूरी तरह एकतरफा निर्णय वाला है, क्योंकि सीईओ जनपद को कोई पूरे मामले का दोषी मानने तैयार नहीं है, इसका कारण भी है, आयोजन में नगर पालिका की भूमिका जनपद से अग्रणी थी, नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का क्रम मंच पर ऊपर था, इस हिसाब से भी बातें यही हो रही हैं कि क्या एसडीएम ने ही सीईओ को निपटारा जिसमें जिला प्रशासन की मंशा सहयोगी बनी।



नियमित सीईओ को आराम, प्रभारी पूर्व को कमान, पहले से तय फार्मूला हुआ सेट

सीईओ जनपद सोनहत किसी कारण से कार्यालय संलग्न हैं, अब मुख्यमंत्री दौरे के बाद दोषारोपण कर बैकूंटपुर सीईओ भी कार्यालय संलग्न किए गए वहीं अब दोनों जगह पूर्व प्रभारी सीईओ काम करेंगे, यह वैसे तो पहले से तय था लेकिन विडंबना यह है कि जिन्हें अब कार्यालय भेज दिया गया है वह नियमित हैं और जो अब हैं वह प्रभारी।



शिला पट्टिकाओं की जिम्मेदारी अन्य विभाग की, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ भी थे जिम्मेदार, फिर कार्यवाही क्यों सीईओ जनपद पर ?

सवाल यह भी कि क्या सीईओ जनपद बैकूंटपुर सही मायने में बलि का बकरा बने, क्योंकि सूत्रों की मानें तो कार्य विभाजन में शिला पट्टिकाओं की जिम्मेदारी अन्य विभाग की थी, एसडीएम बैकूंटपुर भी एक अन्य जिम्मेदार थे, लेकिन जब कार्यवाही की बात सामने आई, सीईओ को निपटारा गया, बताया तो यह भी जा रहा है कि एसडीएम ने सीधे सीईओ का ही नाम लेकर खुद को बरी कराने का प्रयास किया जबकि इतना बड़ा अनुविभाग नहीं है कि एसडीएम एक बार जाकर मैदान निरीक्षण नहीं कर सकते थे, वह नगर पालिका सीएमओ को नहीं कह सकते थे, नगर पालिका अधिकारी भी मामले में जिम्मेदार हैं यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आयोजन में नगर पालिका को जिला जनपद से ऊपर का दर्जा मिला था।

राजस्व विभाग क्या फोटोग्राफी तक की जिम्मेदारी के लिए तैनात था, श्रेय के लिए उपलब्ध था ?

पूरे मामले में पहला सवाल यह है कि क्या आयोजन में सफलता के लिए राजस्व विभाग जिम्मेदार माना जाता और असफलता के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाया जाता या पहले से तय था? सवाल इसलिए क्योंकि जब वन विभाग के विश्राम गृह में पहली बार चूक हुई जो राजस्व विभाग की अतिथि सत्कार चूक थी तब मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई और एक मंत्री वरिष्ठ के साथ देर रात हुई बहस माफी से निपटा ली गई वहीं जब मैदान में शिलान्यास शिला पट्टिकाओं की स्थिति सामने आई जनपद सीईओ को सीधे निपटा दिया गया, क्या यह न्याय का ऐसा पहलू है जहां राजस्व विभाग का दूध भात है?

सीईओ जनपद बैकूंटपुर को हटाने की पहले से थी तैयारी, अवसर को भुनाया गया ?

वैसे तो लोगों का दावा है कि बैकूंटपुर जनपद सीईओ जिला प्रशासन की आंख की किरकिरी बने हुए थे, क्योंकि वह राज्य शासन से सीधे नियुक्त थे जबकि पुराने प्रभारी जनपद सीईओ को लेकर गोलबंदी जारी थी इसलिए इस मौके पर सीईओ बैकूंटपुर जनपद को निपटारा गया, अवसर समझकर पूरे मामले में अपने चहेते को उपकृत किया गया, सीईओ जनपद बैकूंटपुर की जगह मन पसंद प्रभारी की चाह में यह कार्यवाही की जानी बताई जा रही है, यह जिले की मुखिया की मंशा वाली कार्यवाही बताई जा रही है।

ऊपर से नीचे तक: जिम्मेदारी का सफर

1. मुख्यमंत्री स्तर

घोषणा और गौरव- मुख्यमंत्री के हाथों हुए शिलान्यास, तालियों की गूंज और विकास की बड़ी घोषणाएं-इन सबने आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व दे दिया, मंच पर जिले के आला अधिकारी मौजूद थे, श्रेय साझा था, तस्वीरें सामूहिक थीं, पर सवाल उठता है-यदि शिलान्यास मुख्यमंत्री स्तर का था, तो उसकी सुरक्षा और गरिमा की जिम्मेदारी किस स्तर की मानी जाए?

2. जिला प्रशासन: श्रेय का केंद्र

पूरे आयोजन का संचालन जिला प्रशासन के हाथ में था, राजस्व विभाग की सक्रियता, समन्वय बैठकें, व्यवस्थाओं का निरीक्षण-सब कुछ व्यवस्थित दिखाया गया, प्रेस नोटों में सफल आयोजन का श्रेय प्रशासन ने स्वयं लिया, लेकिन जब टूटी पट्टिकाओं का वीडियो वायरल हुआ, तब यही प्रशासन कार्रवाई मोड़ में आ गया, अब श्रेय की जगह संतुलन साधने की कोशिश शुरू हुई, व्यंग्य यही कहता है-सफलता की तस्वीर सामूहिक, गलती की फाइल व्यक्तिगत।

3. अनुविभागीय स्तर (एसडीएम)

निरीक्षण या निष्क्रियता?- आयोजन स्थल संबंधित अनुविभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, एसडीएम स्तर पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी स्वाभाविक मानी जाती है, क्या आयोजन के समापन के बाद स्थल का निरीक्षण हुआ? क्या नगरपालिका और अन्य विभागों के साथ समन्वय हुआ? यदि हुआ, तो चूक कैसे हुई? और यदि नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी मानी जाए?

4. नगरपालिका: मंच पर अग्रणी, मैदान में मौन ?

नगरपालिका को आयोजन में प्रमुख भूमिका दी गई थी, मंचीय प्रतिनिधित्व से लेकर स्थल व्यवस्था तक उसकी भागीदारी बताई गई, तो फिर शिलान्यास पट्टिकाओं की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी किसके हिस्से आई? क्या यह केवल जनपद पंचायत का दायित्व था?

5. जनपद सीईओ : बलि का बकरा या वास्तविक दोषी ?

अब चर्चा का केंद्र जनपद सीईओ है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें लापरवाही का दोषी मानते हुए हटाने की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है, क्या पूरे आयोजन की कमान उनके पास थी? क्या कार्य विभाजन स्पष्ट था? क्या अन्य जिम्मेदारों पर समान स्तर की कार्रवाई हुई? जिले में यह भी चर्चा है कि पहले से प्रशासनिक असहमति थी और अवसर मिलते ही कार्रवाई की गई, यदि ऐसा है, तो यह चूक नहीं, चाल कहलाएगी।

ट्रान्सपोर्ट में दो महीने की 'चुप्पी': नकली दवा मामले में देरी...दस्तावेज और दंड पर बहस

- ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि इंदौर की लोहा मंडी से मां बिजासन ट्रेंडिंग कंपनी द्वारा एक साल में पांच पार्सल भेजे गए, चार पार्सल एक ही नाम— 'प्रेम प्रकाश एजेंसी'—पर। और पाँचवाँ, 24 सितम्बर 2025 का पार्सल, अचानक 'सरस्वती मेडिकोज, सारांरुढ़' के नाम, ट्रांसपोर्टर: नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 29 सितम्बर को पार्सल रायपुर पहुंचा, और फिर... दो महीने तक

सांराङ्ग, यमगढ़ जिले में है, जिसकी दूरी करीब 150-200 किमी है, सवाल यह कि कितनी कठिनाई का सामना कर लेता था तो सीधे स्थानीय रक्त क्यों नहीं? गणपतुनूं टुंगोंपर में क्यों? सुत्रों का दावा है- ‘उत्सवने वाला नेटक’ एक ही था, नाम अलग-अलग पेटान। यह दावा जांच के अधीन है, पर सांराङ्ग पर नजर डालें तो सवालवाले कहते हैं, बताया जाता है कि वल्लभ संस्मृत मोबाइल में देवार्यों की तस्वीरों में मिली-जिहनें कथित तौर पर किसी सीमा एजेन्सी ने साझा किया था, मोबाइल लुट्टा प्रकृत हुआ, पर डिजिटल फॉरेंसिक की जांच पर हस्त्या सर्वजनिक नहीं हुई।

10 दिसंबर 2025 की जल्ती एक घटना है, पर उससे जुड़े सवाल एक कथा बन चुके हैं, नाम बदलने का पैटर्न ट्रांसपोर्ट में महीनों की

हीने के बाद देवजी बड़ा नक्सली था, जिसने सरेंडर किया है। देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर किया है, ऐसी सूचना मिली है। कुछ नाम और शेष हैं, जो निष्क्रिय हैं, उन्हें भी सरेंडर कराया जाएगा। मुख्य धारा से वो जुड़े, इसमें काम किया जा रहा है। बैंक की राशि, शाही-निवाह, खेती करें। इसकी व्यवस्था भी कराई जा रही है।